फा.सं. 1704813/1/2022-मा. (समन्वय) (ई-21449)
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

चंद्रलोक बिल्डिंग
ग्राउंड फ्लोर, 36, जनपथ, नई दिल्ली
दिनांक 08 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **मत्स्यपालन विभाग द्वारा फरवरी, 2024 माह के दौरान किए गए प्रमुख गतिविधियों और महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार मंत्रिमंडल सचिवालय को परिचालित करने के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 19 अगस्त, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/26/1/2018-कैब का संदर्भ लेने और फरवरी, 2024 माह के लिए मत्स्यपालन विभाग का मासिक सारांश परिचालित करने का निदेश हुआ है जिसमें की गई प्रमुख गतिविधियां,महत्वपूर्ण निर्णय और मंत्रिमंडल समिति/ समितियों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में प्रगति सूचनार्थ संलग्न है।

यथोक्त: संलग्नक

(डॉ. एंसी मैथ्यू एनपी)
सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी)

प्रति
मंत्रिमंडल के सभी सदस्य

प्रतिलिपि
1. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110001 (ध्यानार्थ: श्री भास्कर दासगुप्ता, निदेशक)
2. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव
3. राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
4. उप-राष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली
5. प्रेस सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
7. सलाहकार, कृषि कार्यक्षेत्र, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली

सूचना के लिए प्रतिलिपि:
1. माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के निजी सचिव
2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए माननीय राज्य मंत्री के निजी सचिव
3. सचिव, मात्स्यिकी के प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
5. मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिवों के प्रधान निजी सचिव
6. तकनीकी निदेशक, एनआईसी डीओएफ को विभाग की वेबसाइट पर संलग्न दस्तावेज अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में फरवरी, 2024 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय एवं प्रमुख उपलब्धियां

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी, 2024 को आयोजित बैठक में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक अगले चार (4) वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के साथ केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई)" को मंजूरी दी। । योजना के प्रमुख घटकों में शामिल हैं क) मात्स्यिकी क्षेत्र को औपचारिक बनाना, ख) कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों तक मात्स्यिकी सूक्ष्म उद्यमों की पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ग) जलीय कृषि बीमा को अपनाने की सुविधा प्रदान करना, घ) मात्स्यिकी क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना और ड़) मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और विस्तारित करना ।

2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी, 2024 को 7522.48 करोड़ रूपये के पहले से स्वीकृत फंड और 939.48 करोड़ रूपये के भारत सरकार की बजटीय सहायता के भीतर 2025-26 तक अगले 3 वर्षों के लिए मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि / फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के विस्तार को भी मंजूरी दे दी।

3. मत्स्यपालन विभाग ने 19 फरवरी, 2024 को केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, डॉ. एल मुरुगन; सचिव (मत्स्यपालन), संयुक्त सचिव, प्रबंध निदेशक, ओएनडीसी और अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। माननीय मंत्रियों ने एक पुस्तिका "फ्रॉम कैच टू कॉमर्स, इन्क्रीजिंग मार्केट एक्सेस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन" भी जारी की। लगभग 50 मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) वास्तवि रूप से कार्यक्रम में उपस्थित थे और सैकड़ों मछुआरे और मत्स्य किसान वर्चुअली शामिल हुए।

4. माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला, ने 23 फरवरी 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), बैरकपुर, कोलकाता द्वारा "सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि को बढ़ावा देना" विषय पर 13वें इंडियन फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर फोरम का उद्घाटन किया गया।

5. माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला ने 28 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में केरल मात्स्यिकी और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कोच्चि, केरल के अन्य हितधारकों के साथ समुद्री मात्स्यिकी, अनुसंधान और विकास के मुद्दों पर चर्चा की ।

6. मत्स्यपालन विभाग के सचिव ने 19 फरवरी, 2024 को प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव श्री प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।

7. मत्स्यपालन विभाग के सचिव ने जलाशय में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई गतिविधियों जैसे केज कल्चर, पेन कल्चर और फिंगरलिंग स्टॉकिंग की समीक्षा करने के लिए 28 फरवरी, 2024 को गेतलसूद बांध, रांची, झारखंड का दौरा किया। उन्होंने केज निर्माता स्थल का भी दौरा किया और मछुआरों, महिला मछुआरों और मत्स्य किसानों से बातचीत की। उन्होंने 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले भारत के विशाल जलाशय संसाधनों की विशाल क्षमता पर प्रकाश डाला और जलाशयों में जलीय कृषि क्षमता के उपयोग के लिए एकीकृत दृष्टिकोण (इंटीग्रेटेड अपप्रोच) का सुझाव दिया ।

8. संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) ने एफआईडीएफ के तहत स्वीकृत नवा-बंदर, मालवाड़ा, सूत्रपाड़ा और वेरावल में चार फिशिंग हार्बर परियोजनाओं और इन तटीय जिलों में पीएमएमएसवाई परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की समीक्षा करने के लिए गुजरात का दौरा किया । इसके अलावा, संयुक्त सचिव ने 10 फरवरी, 2024 को तटीय शहर सोमनाथ और वेरावल फिशिंग हार्बर के आसपास के स्थानों में फिश मार्केट्स और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी दौरा किया।

9. संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) ने 16 फरवरी, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससीसीसी) की 18वीं बैठक में भाग लिया।

10. संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम (बीओबीपी) - अंतर सरकारी संगठन (आईजीओ) के सहयोग से 19 फरवरी, 2024 को कोच्चि में आयोजित 'भारत में शार्क के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' पर हितधारक परामर्श में भाग लिया।

11. संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) ने 21 फरवरी, 2024 को नीति आयोग में ब्लू इकोनॉमी और महासागर प्रशासन पर भारत-फ्रांस रोड मैप के तहत पहली वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता पर अनुवर्ती चर्चा में भाग लिया।

12. संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) 24 फरवरी को कोलकाता में आईसीएआर-सीआईएफआरआई द्वारा आयोजित 13वें भारतीय फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर फोरम में शामिल हुए और एक्वाकल्चर उद्योग पर एक सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें भारत सरकार की चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों और सरकार से आवश्यक सहायता के साथ अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

13. कृषि भवन, नई दिल्ली में यूरोपीय संघ और भारत के संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) ने 22 फरवरी, 2022 को संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) और यूरोपीय आयुक्त सुश्री सेलीन इदिल की सह-अध्यक्षता में सतत मात्स्यिकी (सस्टेनेबल फिशेरीस) और जलीय कृषि सहित समुद्री मुद्दों पर बैठक की।

14. संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) ने 26-29 फरवरी, 2024 के दौरान अबु दाबी में डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मेलन में सहभागिता की ।

15. संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) ने 28 फरवरी, 2024 को प्रोग्राम लीडर सुश्री नथालिया के नेतृत्व में विश्व बैंक टीम के साथ एक बैठक की, जिसमें विश्व बैंक सहायता प्राप्त, स्वीकृत नई योजना प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को शुरू करने के लिए रोडमैप के साथ-साथ तैयारियों और कार्य योजना पर चर्चा की गई।

16. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने मुख्य कार्यकारी (प्रभारी), एनएफडीबी की अध्यक्षता में तीन परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकें आयोजित और 278.98 करोड़ रूपये की कुल लागत के साथ दीव और दमन, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, केरल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, गुजरात द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) -2023-24 प्रस्ताव को तथा त्रिपुरा में सभी लाभार्थी गतिविधियों और वनकबारा फिशिंग हार्बर से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को मंजूरी दी।

17. एनएफडीबी ने फरवरी, 2024 के दौरान क्रमशः 44,950 और 44,600 व्यक्तियों को कवर करते हुए 14 प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियाँ और 44 आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित कीं।

18. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) के दो फिशिंग वेससेल्स ने माह के दौरान भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में और उसके आसपास मात्स्यिकी संसाधनों और समुद्री स्तनपायी सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिए खोजपूर्ण सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

19. मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत तटीय जल कृषि प्राधिकरण (सीएए) चेन्नई ने देश में 100% फार्म पंजीकरण हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। पंजीकरण की आवश्यकता पर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने का पहला अभियान 14 फरवरी, 2024 को नागापट्टिनम, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था।

20. तटीय जल कृषि प्राधिकरण ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 482 आवेदनों सहित 570 आवेदनों पर कार्रवाई की और इनपुट निर्माताओं से एंटीबायोटिक मुक्त एक्वा इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 83 आवेदन प्राप्त हुए। फर्म्स और हैचरियों में 700 दौरे किए गए और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में सीएए दिशानिर्देशों के अनुपालन पर हितधारकों को जागरूक किया गया।

21. केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान / सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी (सीआईसीईएफ) ने चार (4) फिशिंग हारबर्स /फिश लैंडिंग सेंटर्स (एफएलसी) का तकनीकी मूल्यांकन किया, अर्थात् कराईकल पुदुच्चेरी में मौजूदा फिशिंग हार्बर का विस्तार; दमन और दीव में बांकाबारा में फिशिंग हार्बर का विकास; तमिलनाडु के चिन्नंगुडी मैलादुथुराई जिले में एफएलसी का उन्नयन और बारमाउथ की ड्रेजिंग; और तमिलनाडु के तंजावूर जिले में चैनल और बारमाउथ की चार ड्रेजिंग।

22. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सिफनेट) ने मछुआरों के आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 11 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 3 नियमित पाठ्यक्रम और 8 अल्पकालिक पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिससे 460 उम्मीदवार लाभान्वित हुए।

23. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान / नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग (निफेट) ने 55 समुद्री मछुआरे महिलाओं/पुरुषों के लिए पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

24. मत्स्यपालन विभाग के लिए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के तहत शिकायत निपटान 29 फरवरी, 2024 तक 96% था।